साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कालमक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 10, अंक : 42 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 21 मई 2025 से 27 मई 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

मुख्यमंत्री ने राज्य संग्रहालय में इमर्सिव एक्सपीरियन्स सेंटर का किया लोकार्पण

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों के प्रति युवाओं की रूचि विकसित करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए जानकारियों का आकर्षक रूप से प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। धरोहरों के संरक्षण के लिए भी अद्यतन तकनीक का उपयोग जरूरी है। इस दृष्टि से राज्य संग्रहालय ने इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर आरंभ करने का नवाचार समयानुकूल है। प्रदेश में स्मारकों और संग्रहालयों में दर्शकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। संग्रहालयों की समृद्ध परंपरा में मध्यप्रदेश जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, उससे देश- दुनिया में प्रदेश की विशेष पहचान बनी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर राज्य संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इमर्सिव एक्सपीरियन्स सेंटर का लोकापर्ण किया तथा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में आयोजित कार्यक्रमों का भी वर्चुअल शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम बदलते दौर के भारत में रह रहे हैं। यह बदलाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। संग्रहालय अब इतिहासकारों और शोधार्थियों के साथ-साथ जनसामान्य के लिए भी रूचि-आकर्षण और ज्ञार्नाजन के केंद्र का रूप ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने राज्य संग्रहालय की सराहना करते हुए कि पर्यटकों के लिए अब भोपाल की यात्रा, राज्य संग्रहालय आए बिना अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्कूल

शिक्षा- उच्च शिक्षा और पर्यटन विकास निगम संयुक्त रूप से स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों के संग्रहालय भ्रमण का संभागवार क्रम बनाएं, इससे विद्यार्थी, प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ेंगे और राज्य संग्रहालय की खुबियों से अधिक से अधिक लोग परिचित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक केंद्रो को जन सामान्य से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर गतिविधयां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के प्रमुख नगरों के मुख्य प्रवेश मार्गों पर महापुरूषों को समर्पित द्वार विकसित किए जा रहे हैं। हमारे देवस्थान अभी तक केवल पूजा-पाठ के लिए जाने जाते थे। प्रदेश में निर्मित हुए महाकाल लोक सहित अन्य लोकों ने मंदिरों को आस्था, श्रद्धा के साथ-साथ लोक रुचि का भी स्वरूप प्रदान किया है । प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, मुद्रा व्यवस्था सहित संपूर्ण जीवन पद्धति उन्नत स्वरूप में थी। नवीनतम तकनीक से इनके संरक्षण और प्रस्तुतीकरण से हमारी समृद्ध धरोहर को वर्तमान और आगामी पीढ़ी की रूचि के अनुकूल बनाए रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य संग्रहालय परिसर में आयोजित 'संग्रहालय मेला' के अंतर्गत पुरातत्व के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने उत्खनन उपकरण के प्रकार और कार्य सहित दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मेले में ऐतिहासिक इमारतों के 3डी प्रिंटिंग और कॉस्टिंग से बने मिनिएचर और पीओपी से बनी मूर्तियों को सराहा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में पहली बार वर्चुअल म्यूजियम केंद्र आंखों देखा का शुभारंभ किया गया, जो आगंतुकों को एक अद्वितीय डिजिटल अनुभव प्रदान करेगा। यह केंद्र इंटरैक्टिव और इमर्सिव तकनीक के माध्यम से बिना किसी फिजिकल गाइड के संग्रहालय की गहन यात्रा का अनुभव कराएगा। इससे दर्शकों को इतिहास को करीब से देखने का अनुभव मिलेगा और वे स्टीरियोस्कोपिक 3-डी में भव्य ऐतिहासिक महलों की एक रोमांचक कहानी यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संचालनालय के अधिकृत मैस्कॉट वाकणकर दादा का लोकार्पण भी किया गया। यह मैस्कॉट प्रसिध्द पुरातत्वविद पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर के कार्यों और योगदान को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के त्रैमासिक न्यूज लैटर ऑफबीट मध्य प्रदेश के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया । मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संचनालय पुरातत्व द्वारा प्रकाशित 11 नवीन पुस्तकों का विमोचन भी किया। इसमें भिंड जिले का पुरातत्व, रतलाम जिले का पुरातत्व, बैतूल जिले का पुरातत्व, बड़वानी जिले का पुरातत्व, कटनी जिले का पुरातत्व, भोपाल के चिचित्र शैलाश्रय, रायसेन के चिचित्र शैलाश्रय, सहित संचनालय का कंजर्वेशन मैनुअल और नियम पुस्तिका शामिल है। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला ने संचालनालय पुरात्व द्वारा जारी गतिविधियों की जानकारी दी।

भोपाल में डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण

भोपाल नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि किसी शहर के संग्रहालय और शिक्षण संस्थान धरोहर के समान हैं इनका समृद्ध होना समाज के गौरव को बढ़ाता है। उन्होंने माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय के गौरवशाली इतिहास की प्रशंसा की। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि आधुनिक युग में नौजवान पीढ़ी के लिये डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा बहुत उपयोगी रहेगी। मंत्री श्री विजयवर्गीय रविवार को भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर डिजिटल लाइब्रेरी के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में संग्रहालय की स्थापना से लेकर अब तक के सफर में सहयोग करने वाली संस्थाओं और हस्तियों का सम्मान किया गया। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उनके इस संकल्प को शैक्षणिक संस्थानों को समृद्ध करके पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सप्रे संग्रहालय की शुरूआत एक छोटे स्वरूप में हुई थी। लगभग पिछले 4 दशकों में इस संस्थान ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर ली है।

तापमान में गिरावट के बावजूद ग्लेशियरों को दोबारा स्थापित होने में लगेंगी सदियां

न्यूयार्क। बड़े ध्रुवीय ग्लेशियरों को तीन डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबरने में कई शताब्दियां लग जाएंगी, आल्प्स, हिमालय और उष्णकटिबंधीय एंडीज जैसे छोटे ग्लेशियर अगली पीढ़ियों तक पहले जैसी नहीं हो पाएंगे इन पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी नीचे की ओर रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर शुष्क मौसम के दौरान। एक नए शोध में लक्ष्य से बाहर के परिदृश्यों के तहत साल 2500 तक ग्लेशियरों में बदलाव का पहला वैश्विक सिमुलेशन किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि ग्रह अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को तीन डिग्री सेल्सियस तक पार कर जाता है और फिर वापस ठंडा हो जाने पर भी पहले जैसी स्थिति नहीं बनेगी। यह शोध ब्रिटेन के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और ऑस्ट्रिया के इंसब्रूक विश्वविद्यालय की अगुवाई में किया गया है। नेचर क्लाइमेट चेंज में 19 मई, 2025 को प्रकाशित शोध से पता चलता है कि ऐसी स्थिति में ग्लेशियरों का द्रव्यमान 16 फीसदी तक अधिक घट सकता है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी नीचे की ओर रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर शुष्क मौसम के दौरान।

शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि वर्तमान जलवायु नीतियां पृथ्वी को तीन डिग्री सेल्सियस के करीब ले जा रही हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसी दुनिया ग्लेशियरों के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा वाली दुनिया से कहीं अधिक बुरी है। शोध का उद्देश्य यह पता लगाना था कि यदि ग्रह फिर से ठंडा हो जाए तो क्या ग्लेशियर फिर से बन सकते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोग पूछते हैं, क्या ग्लेशियर हमारे जीवनकाल में या हमारे बच्चों के जीवनकाल में फिर से बनेंगे? शोध के निष्कर्षों से पता चलता है कि दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होने वाला है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी नीचे की ओर रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर शुष्क मौसम के दौरान। दुनिया भर में तापमान में वृद्धि के लिए एक दशक पहले अपनाई गई पेरिस समझौते की सीमाओं का अब पार करने का बड़ा अंदेशा है। उदाहरण के लिए, पिछला साल पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म साल था और 1.5 डिग्री सेल्सियस के निशान को पार करने वाला पहला कैलेंडर वर्ष था। जलवायु वैज्ञानिकों ने भविष्य में ग्लेशियर के विकास का आकलन एक मजबूत लक्ष्य से बाहर या ओवरशूट परिदृश्य के तहत किया है, जिसमें वैश्विक तापमान 2150 तक 3.0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ना जारी रहेगा, 2300 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरकर स्थिर हो जाएगा। यह परिदृश्य नेट-जीरो भविष्य को दर्शाता है, जिसमें कार्बन कैप्चर जैसी अनचाही उत्सर्जन तकनीकें केवल बढ़ते तापमान की सीमा के पार होने के बाद ही तैनात की जाती हैं। शोध के परिणामों से पता चलता है कि ग्लेशियरों का प्रदर्शन उस दुनिया की तुलना में बहुत खराब होगा, जहां तापमान की सीमा पार हुए बिना 1.5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हो जाता है। जिसमें 2200 तक ग्लेशियर द्रव्यमान का अतिरिक्त 16 फीसदी और 2500 तक 11 फीसदी से अधिक गायब हो जाएगा। अतिरिक्त पिघला हुआ पानी आखिरकार समुद्र तक पहुंच जाएगा, जिससे समुद्र के स्तर में और भी अधिक बढ़ोतरी होगी। शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि मॉडल दिखाते हैं कि बड़े ध्रुवीय ग्लेशियरों को तीन डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबरने में कई शताब्दियां लग जाएंगी। आल्प्स, हिमालय और उष्णकटिबंधीय एंडीज जैसे छोटे ग्लेशियर अगली पीढ़ियों तक पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन 2500 तक ऐसे होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी नीचे की ओर रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर शुष्क मौसम के दौरान। जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो वे अस्थायी रूप से अधिक पानी छोड़ते हैं, एक ऐसी घटना जिसे ग्लेशियर %पीक वॉटर% के रूप में जाना जाता है। शोध पत्र में कहा गया है कि यदि ग्लेशियरों का फिर से विकास होता है, तो वे फिर से बर्फ के रूप में पानी जमा करना शुरू कर देते हैं और इसका मतलब है कि नीचे की ओर पानी कम बहेगा। इस प्रभाव को %ट्रफ जल% कहते हैं, जो कि चरम जल के विपरीत है। शोध में जिन बेसिनों का अध्ययन किया गया है, उनमें से लगभग आधे में 2100 के बाद किसी न किसी रूप में ट्रफ जल का अनुभव होगा। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अध्ययन ग्लेशियर से संबंधित जल प्रणालियों और समुद्र-स्तर में वृद्धि के लिए तापमान की सीमा के पार होने के कई और जटिल परिणामों को समझने की दिशा में पहला कदम है। शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, चाहे अस्थायी रूप से ही क्यों न हो इसके कारण सदियों तक ग्लेशियरों के नष्ट होने के आसार बने रहते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि इस नुकसान को आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है, भले ही तापमान बाद में सुरक्षित स्तरों पर वापस ही क्यों न आ जाए। हम उत्सर्जन में कटौती में जितनी देर करेंगे, भविष्य की पीढ़ियों पर उतना ही अधिक बोझ डालेंगे, जिसे बदला नहीं जा सकता है।

बारिश से पहले अभियान, रोज 1000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लक्ष्य

इंदौर बारिश से ठीक पहले नगर निगम ने भूजल स्तर सुधारने पर काम शुरू किया है। शनिवार को निगमायुक्त शिवम वर्मा ने सभी जोनल अधिकारियों और विभाग प्रमुखों की बैठक में बारिश से पहले 25 हजार रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने का लक्ष्य तय किया है। लक्ष्य पूरा करने के लिए शहर में प्रतिदिन करीब 1 हजार और हर जोन में 35 से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने होंगे। वर्मा के मुताबिक, जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज सॉफ्ट कराने के लिए शनिवार को स्मार्ट सिटी ऑफिस में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में 25 हजार से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया है। इस दौरान हर जोन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। चेतावनी दी है कि लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले जोनल अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि इस काम को मिशन के रूप में लें। कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा सुनिश्चित करने के लिए निगम के रजिस्टर्ड प्लंबरों से ही काम कराया जाए। रहवासियों एवं संस्थानों से चर्चा कर जनसहयोग लें। निर्माण में वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल हो।

अर्बन फ्लड की पहचान करने में मददगार होगा आईआईटी कानपुर की यह प्रणाली

कानपुर आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (एसआइइसी) से जुड़े स्टार्टअप टेरएक्रा यूएवी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने शहरी बाढ़ प्रबंधन यानी अर्बन फ्लड के मैनेजमेंट के लिए एक उन्नत आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली की शुरुआत की है। यह परियोजना वैश्विक डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेवा प्रदाता एनटीटी डाटा के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत संचालित की जा रही है और जलवायु अनुकूल शहरी विकास की दिशा में एक ठोस पहल मानी जा रही है।

इस परियोजना का केंद्र बिंदु एक वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म है, जो ड्रोन से ली गई उच्च-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरों और उपग्रह रिमोट सेंसिंग डेटा को एकीकृत करता है। यह प्रणाली बाढ़ के सटीक मानचित्रण, पानी भराव के अनुमान और प्रभावित आबादी के आकलन में सक्षम है। इसके माध्यम से नीति-निर्माताओं को आपदा प्रबंधन के लिए समय रहते ठोस निर्णय लेने में मदद मिलती है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गंगा बैराज के आसपास के 24 बाढ़ संभावित गांवों का सर्वेक्षण किया गया, जिससे ग्राम स्तर का सूक्ष्म डेटा जुटाया गया जो आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में बेहद उपयोगी साबित हो सकता है इस परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और कानपुर विकास प्राधिकरण भी शामिल हुआ। उनका कहना था कि यदि इस परियोजना को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए, तो यह बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी और समय रहते चेतावनी प्रणाली के निर्माण में अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। साथ ही शहरी नियोजन के दृष्टिकोण से यह प्रणाली बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने और बुनियादी ढांचे व आबादी पर संभावित खतरे का आकलन करने में भी मददगार होगी कानपुर मंडल आयुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन ने कहा, आईआईटी कानपुर द्वारा शुरू की गई यह परियोजना क्षेत्र के लिए बेहद लाभकारी होगी। यह प्रणाली ड्रोन और सैटेलाइट दोनों तकनीकों का उपयोग कर बाढ़ प्रतिक्रिया को मजबूत करती है। इससे बाढ़ की संभावनाओं का पहले ही पता लगाना संभव होगा, जिससे समय रहते बचाव के उपाय किए जा सकेंगे और बड़े नुकसान से बचा जा सकेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इस परियोजना को पूरे कानपुर जिले और फिर प्रदेश के अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में विस्तारित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह तकनीकी पहल खास तौर से किसानों के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि यह फसलों को बाढ़ जनित नुकसान से बचाने में मदद कर सकती है आईआईटी कानपुर के एसआइइसी के सीईओ अनुराग सिंह सीईओ ने कहा, टेरएक्रा यूएवी जैसे डीप-टेक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना एसआइआइसी की प्रतिबद्धता है। यह परियोजना इस बात का उदाहरण है कि कैसे उद्योग जगत के अग्रणी संस्थानों जैसे एनटीटी डाटा के साथ रणनीतिक साझेदारी नवाचारों को समाज के लिए उपयोगी समाधानों में बदल सकती है एनटीटी डाटा की ग्लोबल सीएसआर गौरी बहुलकर ने कहा, जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में। इस सीएसआर सहयोग के माध्यम से हमारा उद्देश्य स्मार्ट गवर्नेंस और सुरक्षित समुदायों को प्रोत्साहित करना है। वहीं, टेरएक्रा यूएवी के संस्थापक और आईआईटी प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने कहा हमारा प्लेटफॉर्म बाढ़ के समय तत्काल निर्णय लेने में उपयोगी भू-स्थानिक डेटा सुलभ कराता है। एनटीटी डाटा के सहयोग से हमने एक ऐसा फ्रेमवर्क विकसित किया है जो यूएवी और सैटेलाइट डेटा को एक सहज डैशबोर्ड में प्रस्तुत करता है। इस प्रणाली का लाइव डेमो आईआईटी कानपुर के पीबीसीईसी परिसर में किया गया।

मुख्यमंत्री का कर्मचारी हितैषी निर्णयों के लिए मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने किया अभिनंदन

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने के लिए सुव्यवस्था स्थापित करना राज्य सरकार का उद्देश्य है। इस मंशा का सफल क्रियान्वयन सरकार के कर्मचारियों पर निर्भर करता है, इस दृष्टि से प्रदेश के कर्मचारी सच्चे कर्म योगी हैं। कर्मचारियों के परिश्रम और समर्पण से ही जनकल्याण और विकास के पथ पर हमारा प्रदेश अग्रसर है। कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा से जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश के अग्रणी राज्य में शामिल हुआ है।

प्रदेश के कर्मचारी सरकार और जनता के बीच नल और नील की तरह सेतु बनाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रवींद्र भवन में मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अभिनन्दन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा गत माह लिए गए कर्मचारी हितैषी निर्णयों के लिऐ मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने रविंद्र भवन में उनका अभिनंदन किया। कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अंगवस्त्रम भेंट कर मुख्यमंत्री डॉ.यादव का तिलक किया। इसके साथ ही उन्हें शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। कर्मचारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री डॉ.यादव को वृहद आकार की मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित करने के बाद मां सरस्वती और पूर्व वरिष्ठ श्रमिक नेता स्व. दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक श्री भगवानदास सबनानी, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत श्रीवास्तव तथा महामंत्री श्री जितेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कर्मचारी संघ की ओर से कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की मांग स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 9 वर्षों से लंबित हाउस रेंट अलाउंस की मांग को भी पूरा किया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों- कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुविधा को देखते हुए प्रदेश में स्थानांतरण नीति का क्रियान्वयन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान का वादा किया था। क्रमबद्ध रूप से सभी समस्याओं का निराकरण किया गया है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान संचालित हैं। पुलिस में सभी पद भरे गए हैं।

जल गंगा संवर्धन जैसे अभियान ही कर सकते हैं जल संकट की वैश्विक चिंता का समाधान

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान पर्यावरण और जल संरक्षण, जल संरचनाओं के पुनरुत्थान और सांस्कृतिक चेतना का समवेत संगम बन गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने इस अभियान' से जल संकट के समाधान के लिये गंभीर पहल की है। जल संकट देश-प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया की चिंता का विषय है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए तो यह जीवन-मृत्यु का विषय है। भविष्य की चिंताओं का समाधान आज के अभियान में जल संवर्धन के प्रयासों में निहित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान एक बहुस्तरीय आयोजन है। इसका उद्देश्य राज्य के जल स्त्रोतों जैसे नदियों, तालाबों, झीलों, बावड़ियों, पुराने कुओं और जलधाराओं को पुनर्जीवित करना और उन्हें सतत रूप से संरक्षित करना है। यह अभियान सरकारी योजना से आगे बढ़कर अब जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है।

उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने जल गंगा संवर्धन अभियान में जबलपुर जिले में जल स्त्रोतों के संरक्षण के लिये संचालित की जा रही गतिविधियों का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने जनपद पंचायत कुंडेश्वर धाम के गुरैया गांव में बने खेत तालाब, कूप रिचार्ज निर्माण और बघराजी गांव में में लैगून पद्धति से जोगी तालाब के विस्तार एवं सुदृढीकरण के कार्य का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने बघराजी में जन समुदाय को संबोधित करते हुए जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में तत्परता से कार्य करने के लिए प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश भर में ताल, तलैया, कुएं एवं बावड़ी सहित विभिन्न जल स्त्रोतों को संरक्षित करने के साथ ही प्राचीन जलस्त्रोतों को सूचीबद्ध कर उन्हें पुनर्जीवित किये जाने का पुनीत कार्य हो रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कुंडेश्वर धाम के साथ ही हनुमान ताल में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। हनुमान ताल के उन्नयन के लिए अमृत योजना के तहत 55 लाख 09 हजार 514 रूपए की लागत से डी-सिल्टिंग, फेंसिंग और एरिएशन के कार्य किए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बुरहानपुर में नया खेड़ा गांव के ताप्ती घाट छोटे पुल पर स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित श्रमदान में नेपानगर विधायक सुश्री मंजू दादू, जनपद अध्यक्ष श्री राकेश सोलंकी, जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत सीईओ सुश्री लता शरणागत, अपर कलेक्टर श्री वीरसिंह चौहान, एसडीएम श्री वाखला, जनपद सीईओ श्रीमती वंदना कैथल, जिला परियोजना प्रबंधक श्रीमति संतमति खलखो, पंचायत विभाग के समस्त अधिकारी-कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित अन्य विभागों के अधिकारीगणों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। श्रमदान करने वालों ने ताप्ती नदी में उतरकर गाद, नदी पुराने कपड़े और प्लास्टिक कचरे को बाहर निकाला। नदी में जमी हरी काई को भी साफ किया गया। अभियान में जल संरक्षण के प्रति नागरिकों और ग्रामवासियों को जागरुक बनाने के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभियान में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता जगाने के लिए दीवार लेखन, जागरूकता रैली, पोस्टर-बैनर, रंगोली, ग्राम सभाएं, कलश यात्राएं, शपथ-ग्रहण सहित अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिले के गांवों में कुओं की मरम्मत, तालाबों का जीर्णोद्धार, डैम्स की साफ-सफाई सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खिरावली तालाब के बंड पर उगे जंगल की सफाई जन सहयोग से की। कर्मचारियों और जन भागीदारी के परिश्रम से इस तालाब को पुनर्जीवन मिला है। अब यह ग्रीष्म ऋतु में भी भरा रहेगा। साथ ही आने वाले मानसून में इस पर्याप्त मात्रा में जल संग्रह होगा और स्थानीय जल स्त्रोतों में भी भू-जल रिचार्ज रहेगा। 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के अंतर्गत जल स्त्रोतों के गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार जैसे कार्य किए जा रहे हैं। अभियान में हरदा के कालू बाबा परिसर में स्थित प्राचीन बावड़ी में जीर्णोद्धार संचालित किया जा रहा है। इस कार्य का निरीक्षण करते हुए जिले के कलेक्टर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्माण वर्षा शुरू होने से पहले पूर्ण कराने के निर्देश दिये। प्राचीन बावड़ी का इतिहास एक बोर्ड पर लिखवाने के लिए भी कलेक्टर ने निर्देश दिया। जनभागीदारी से जन्मा भागीरथी संकल्प का प्रतीक यह अभियान भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित, समृद्ध और जल-सम्पन्न मध्यप्रदेश में जुटा जन-आंदोलन बन गया है।

सिंहस्थ से पहले शिप्रा में मिलने से रोकेंगे कान्ह नदी का गंदा पानी

इंदौर. कान्ह नदी का गंदा पानी शिप्रा में मिलता है। इसके प्रवाह को रोकने सरकार अब सांवेर में स्टॉप डैम बनाने जा रही है। छह स्टॉप डैम का टेंडर जारी हो गया है। कम कीमत पर बनाने वाले ठेकेदारों को 15 माह में काम पूरा करके देना है।

सिंहस्थ 2028 को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। महाकुंभ के दौरान मोक्षदायिनी मानी गई मां शिप्रा में स्नान का खासा महत्व है। शिप्रा में इंदौर की कान्ह नदी का गंदा पानी बहकर पहुंचता है। भले ही वह ट्रीटमेंट प्लांट से होकर गुजरता है, लेकिन वह सिर्फ पेड़-पौधों की सिंचाई के उपयोग तक ही सीमित है। इसे रोकने जल संसाधन विभाग ने सांवेर में छह स्टॉप डैम निर्माण की योजना बनाई है। पांच डैम कान्ह नदी और एक शिप्रा नदी के मुहाने पर बनेगा। सभी के लिए ठेकेदार कंपनियां भी तय हो गई हैं, जिनसे अनुबंध होने जा रहा है। सभी को निर्माण के लिए 15 माह का समय दिया है। कुछ स्टॉप डैम छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी ताकि भविष्य में दिक्कत न हो। तीन स्टॉप डैम ओर हैं जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति हो गई है, लेकिन टेंडर जारी नहीं किए गए। कान्ह नदी के पानी को रोकने के लिए लालाखेड़ा के स्टॉप डैम की 53 लाख में मरमत कराई जाएगी। मेकमलमा बैराज सहपुरिया में शिप्रा के पानी को रोकने लिए स्टॉप डैम बनना है तो ग्राम बुढ़ी बरलाई में 14.66 करोड़ की लागत से घाट बनाया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008